New Airports in the country

178. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up new airports in the country considering, the demands from various States; and

(b) if so, what are the places selected for construction of new airports in the country and the amount allocated by Government for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Development of new airports is taken up depending upon the demand from the airlines and the capacity available with them, traffic potential and the availability of resources for development of infra-structural facilities.

(b) Presently the National Airports Authority is developing new airports at Shimla (Himachal Pradesh), Calicut (Kerala) and Agatti (Lakshadweep Island). The likely cost of development of these airports is indicated below against each of them:

(i) Shimla....Rs. 4.21 crores
(ii) Calicut....Rs. 22.41 crores
(iii) Agatti....Rs. 6.81 crores.

महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते

179. **श्री शरद यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को अन्य निगमों के कर्मचारियों की भांति वेतन और भत्ते दिए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) इस संबंध में नियमों को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जाएगा;

(घ) क्या इस संबंध में कोई समिति गठित की गई है;

(ङ) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, उप-प्रबंधक (प्रचार), सहायक प्रबंधक (जन सम्पर्क) और आशुलिपिकों आदि को वेतन और भत्ते केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों के अनुसार मिल रहे हैं या निगमों के वेतनमानों के अनुसार;

(च) यदि उन्हें निगमों के वेतनमानों के अनुसार वेतन और भत्ते मिल रहे हैं तो उनका श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(छ) प्रत्येक मामले में इन दोनों वेतनमानों का अन्तर कितना है;

(ज) क्या निगम के अन्य कर्मचारियों की भी इन अधिकारियों के समान वेतन दिए जाने की संभावना है; और

(झ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) निगम के प्रबंध निदेशक को वेतन और भत्ते सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को देय वेतन और भत्तों के अनुसार दिए जा रहे हैं। उप-प्रबंधक (प्रचार), सहायक प्रबंधक (जन संपर्क) तथा स्टेनोग्राफर आदि को वेतन और भत्ते केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे हैं।

(च) निगम के प्रबंध निदेशक अनुसूची "क" के वेतनमान अर्थात 4,500–125–5000 रु० में आते हैं तथा उन्हें इस वेतनमान पर तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित औद्योगिक मंहगाई भत्ता और अंतरिम राहत दी जाती है।

(छ) केन्द्र सरकार में प्रबंध निदेशक का कोई पद नहीं है। इसकी वजह से, उनके मामले में तथा अन्य के संबंध में उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) और (झ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) का उत्तर ही लागू होता है।

Affairs of Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi

180. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether as per the Memorandum of Association and Rules of Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi there is provision of auditing of accounts of the Institute by the Auditor appointed from the panel of Government approved Auditors;

(b) whether the Institute has forwarded a panel of three private Auditors to Union Government for its approval;

(c) whether prior to according Deemed Unversity Status to the Institute its accounts were not audited by Accountant General, Bihar in spite of such provision in the Rules of the Institute;

(d) whether alleged misappropriation of Government grants as well as Institute funds has been reported to Government; and

(e) if so, whether Government propose to approve a panel of Auditor consisting of Accountant General, Bihar and Auditor General, India for auditing the accounts of the Institutes?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The accounts of the institute have been regularly audited by an approved firm of Chartered Accountant appointed by the Board of Governors of the institute. Accountant General Bihar has also carried out the inspections of accounts concerning Government grants.

(d) Complaints were received demanding an enquiry into the affairs of this institute. The matter was examined by a high powered committee and it was of the view that funding of the institute is by and large along the right line.

(e) Proposal of the Board of Governors of the Institute for appointment of Auditors is under consideration.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मामलों की जांच

181. **श्री शरद यादव :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री राज्य सभा में 25 फरवरी, 1987 को अतारांकित प्रश्न 297 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र संघ, नागरिक संघ, शिक्षक संघ व कर्मचारी संघ की मांग पर विश्वविद्यालय में विजीटोरियल जांच कराये जाने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मामलों में विजीटोरियल जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के बेहतर प्रबन्ध के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करने के लिए पहले ही एक समिति गठित की है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अनुदान

182. **श्री शरद यादव :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कटौती की गई है; और